International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

दक्षिण एशिया में संघर्ष

दक्षिण एशिया– एक परिचय

हरीश कुमार यादव
शोध छात्र
राजनीतिशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
Email-harishmuir74@gmail.com

किसी भी क्षेत्र के कई लक्ष्यार्थ (Connotations होते) हैं। भौगोलिक तौर पर एक क्षेत्र (Region) किसी देश से बड़ा और महाद्वीप से छोटा होता है।

वैचारिक द्वंद, सामरिक प्रभुता, राष्ट्रीय हितों का पोषण, राष्ट्रीय शक्ति का निरंतर संवर्द्धन एवं संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष आदि सभी तत्व अंर्तराष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष की प्रकृति में समाहित विशिष्ट तत्व हैं और दक्षिण एशिया का क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। इस क्षेत्र में होने वाले नृजातीय संघर्ष, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववादी आंदोलन, परमाणु प्रसार आंतरिक के साथ–साथ वाह्य सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं।

यह क्षेत्र 4 इस्लामिक गणतंत्र, 2 लोकतंत्र बौद्ध बहुसंख्यक आबादी के साथ और 2 लोकतंत्र हिंदू बहुसंख्यक आबादी को खुद में समेटे है।

जिसमें भारत व श्रीलंका जहाँ लोकतंत्र के 70 वर्ष के साक्षी हैं वहीं पाकिस्तान व बांग्लादेश में लोकतंत्र व सैन्य शासन के बीच व्यवस्था झूलती रहती है। नेपाल अपने लंबे राजशाही के इतिहास का अंत कर लोकतंत्र के स्वरूप को अपनाने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मालदीव इस क्षेत्र का एक छोटा सा द्वीप है जिसने 1968 में खुद को गणतंत्र घोषित किया था। 800 साल की लंबी राजशाही को समाप्त

करके। लंबे नागरिक युद्ध, राजशाही और कट्टर तालिबानी शासन के पश्चात् आज अफगानिस्तान राष्ट्रपति अशरफ घनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणतंत्र के तौर पर राष्ट्र निर्माण के पथ पर अग्रसर है।

किंतु इस क्षेत्र की कुछ साझा समस्याओं, आर्थिक–सामाजिक विषमताओं, जेन्डर, धार्मिक, भाषायी, जातीय एवं अलगाववादी विचारधाराओं ने इस क्षेत्र की लोकतांत्रिक, बहुलवादी, अनुनादी (Vibrant) राजनीतिक संस्कृति को छिन्न–भिन्न कर दिया है। वर्तमान में दक्षिण एशिया के क्षेत्र में 4 'H' Human Being, Human Right, Human Security और Human Development की समस्या एक बड़ी चुनौती की भांति खड़ी है।

वैश्विक राजनीति में दक्षिण एशिया का महत्व

विविध संस्कृतियों को खुद में समेटे आठ राज्य, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा, प्रमुख धर्मों (Religions) के अनुयायियों की उपस्थिति यह सब तत्व कुछ विशेष विशेषता प्रदान करते हैं दक्षिण एशिया को।

वैश्विक राजनीति में दक्षिण एशिया क्षेत्र की महत्वता है क्योकि–

- अपनी भू–स्त्रातेजिक (Geo Strategic) और भू–राजनीतिक (Geopolitical) स्थिति के कारण यह क्षेत्र विस्फोटक के साथ–साथ असीम सम्भावनाओं व अवसरों से भी युक्त है।
- बड़ी शक्तियों (Great Powers) की इस क्षेत्र में दिलचस्पी एवं हस्तक्षेप का इतिहास

- 9/11 की घटना के बाद यह क्षेत्र आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की भूमि बन गया है।
- दुनिया इसे एक बड़े आकर्षक बाज़ार, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और सस्ते श्रम की मांग को पूरा करने वाले क्षेत्र के तौर पर देखती है।

संघर्ष–

अपने मूल्यों, हितो व जरूरतों के विपरीत होने पर किये गए या किए जाने वाले प्रतिरोध को हम संघर्ष (Conflict) के तौर पर परिभाषित कर सकते हैं। यह संघर्ष आंतरिक भी हो सकता है और वाह्य भी यह दो पक्षों के मध्य भी हो सकता है और इसका स्वरूप बहुपक्षीय भी हो सकता है।

एक संकल्पना के तौर पर संघर्ष कई प्रकार के दृष्टिकोण/अवस्था (aspects) को परिभाषित करता है सामाजिक असहमति, हितों का संघर्ष, विशिष्ट (Individual) समूह (Groups) एवं संगठन (Organizations) के मध्य संघर्ष। राजनीतिक भाषा में कहें तो संघर्ष को हम युद्ध, क्रांति और अन्य संघर्षो के रूप में देख सकते है जिसमें बल का भी प्रयोग होता है और यह संघर्ष सशस्त्र संघर्ष तक भी विस्तारित हो सकता है।

संघर्ष के प्रकार–

विश्व के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र में व्याप्त संघर्षो को मुख्यतः 4 वर्गो में विभाजित कर सकते हैं–

(1) वैश्विक राजनीति, रणनीति के तहत थोपे गए व विस्तारिक किए गए संघर्ष, इसमें विश्व राजनीति की बड़ी शक्तियों (Great Powers) की भूमिका भी शामिल है।

(2) वे संघर्ष जो इस क्षेत्र के राज्यों को विरासत में मिले।

(3) राजनीतिक उग्रता, सामाजिक–सांस्कृतिक विकृति एवं विकासात्मक पंगुता द्वारा जन्मे एवं पोषित संघर्ष।

(4) गैर–राज्यीयकर्ता (Non-State Actors) द्वारा जनित एवं संचालित संघर्ष।

प्रथम वर्ग में संघर्ष को अधिरोपित (Inflicted) करने वाली ताकत व तत्व। क्षेत्र से बाहर होते हैं उदाहरण– 9/11 की घटना के बाद अफगानिस्तान में अमरीका का हस्तक्षेप और इस हस्तक्षेप को 'आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई' का नाम देकर इस क्षेत्र में सैन्य जमाव व युद्ध जैसे 1979–80 में USSR का हस्तक्षेप।

दूसरी श्रेणी में भारत–पाक के मध्य व्याप्त संघर्षो को देख सकते हैं। तमाम प्रकार के नृजातीय (Ethnic), सांप्रदायिक (Sectarian) विद्रोहों को तीसरी श्रेणी में रख सकते है और चौथे वर्ग में आतंकी संगठन आते है जिन्होंने 2008 के मुंबई बम धमाकों जैसे नृशंस कृत्य किए हैं। इन सभी श्रेणियों में शामिल संघर्ष सशस्त्र भी हो सकते हैं और हिंसक भी, साथ ही साथ राजनीतिक चिंता को उजागर भी करते हैं। यह अहिंसक भी हो सकते हैं साथ ही बेहद प्रचलित भी।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

संघर्ष प्रबंधन (Conflict Management) का विज्ञान और कला भी इस बात पर ध्यान केन्द्रित करती है कि कैसे हिंसक संघर्ष को अहिंसक संघर्ष में बदलें और कैसे किसी अहिंसक संघर्ष को हिंसक संघर्ष में बदलने से रोकें। राज्यों के मध्य (Interstate) संघर्ष की स्थिति का कारण कई बार सीमा–विवाद, संसाधनों यथा पानी, मत्स्यन जैसे संसाधनों पर असहमति या किसी पक्ष को रोकने, व्यापार, निवेश से सम्बन्धित मुद्दों पर मतभेद, नागरिकों द्वारा अवैध प्रवसन। चतुर्थ श्रेणी में शामिल संघर्षो का सम्बन्ध गैर राज्य कर्ताओं (Non-State Actors) से है। जिन्होंने पिछले कुछ सालों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। विशेषकर 9/11 के बाद अल–कायदा जैसे संगठन ने U.S.A. पर जब आतंकी हमला किया। जिसने इस बात की स्थापना मज़बूती से की कि ये किसी भी स्थापित राज्य की मदद के बिना भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भेद कर आतंकी कृत्य को अंजाम दे सकते हैं।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

Non-State Actor's की इन्ही भूमिका को रेखांकित करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री शिवशंकर मेनन ने IPCS Conference 2012 में कहा था कि–

Today, there is a fundamental change in the nature of conflict, which is not just evolving from one stage to another, but is undergoing change as a result of shift in the character of a conflict. The age of global interdependence has ensured the decline in conflicts between states. Nevertheless, there is escalation in the conflicts involving non-state actors, particularly when the lines between state and non-state actors are considerably becoming vague... The cocktail of NGOs, social media and the like, as spotted in West Asia, induce kinetic and physical consequences ultimately culminating in regime changes. In addition, the technology has also empowered the non-state actors to pose an important challenge to the state. The obliteration of distinction between state and non-state actors along with the punctured boundaries of state sovereignty has created new situations demanding novel perspectives

दक्षिण एशियाई देशों में संघर्ष–

पाकिस्तान :- अपने जन्म के साथ ही अर्थात 1947 के बाद से लगातार एक राज्य के रूप में पाकिस्तान विभिन्न प्रकार की चुनौतियों यथा राष्ट्रवादी कट्टरता, क्षेत्रीय अलगाववाद (Regional Separatism), धार्मिक सिद्धांत (Religious doctrine) और राजनीतिक विचारधारा (Political ideology) से जूझ रहा है।

यह अस्थिरता पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में दिखती है जहाँ लोकतंत्र की गति को सैन्य शासन ने बाधित किया। हाल ही में यह पहला मौका था जब एक लोकतांत्रिक सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांरण किया।

किंतु पाकिस्तान की आंतरिक व बाहरी राजनीतिक नीतियों में वहाँ की सेना का हस्तक्षेप दिखता है। वस्तुतः इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तानी जनमानस के समक्ष इस बात को स्थापित करने की कोशिश में जुटी रहती है कि वह राष्ट्रीय हित के प्रति सदैव सतर्क व संवेदनशील है और इन सबसे बढ़कर वह पाकिस्तान के कुव्यवस्थित लोकतंत्र का प्रभावी विकल्प है।

राजनीति में सेना के दखल के अतिरिक्त घरेलू कट्टरवाद व आतंकवाद दक्षिण एशिया के साथ–साथ स्वयं पाकिस्तान के लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं। फिर चाहे वो लाल मस्जिद की खूनी लड़ाई हो जिसमें इस्लामी कट्टरपंथी और सेना आमने–सामने थीं अथवा दिसम्बर 2014 में पेशावर के स्कूल पर आतंकी हमला जिसमें अधिकांशतः मासूम बच्चे आतंक की भेंट चढ़ गए थे। इसी वर्ष (2014) में पाकिस्तान की सेना द्वारा आतंक के विरूद्ध आपरेशन जर्ब–ए–एज्ब प्रारंभ किया गया किंतु यह भी नाकाफी साबित हुआ है।

बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान की राजनीति व आतंरिक संघर्ष का मुद्दा रहा था जो अब वर्तमान में पाकिस्तानी सीमा की रेखा से बाहर आ गया है। इसका स्पष्ट प्रमाण तब मिला जब भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2016 को लाल किले से भारतीय जनमानस को सम्बोधित करते हुए बलूचिस्तान का जिक्र किया।

बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के करीब एक रणनीतिक क्षेत्र है। पाकिस्तान के कुल क्षेत्र का यह 43 प्रतिशत है, लेकिन यहाँ केवल 5 प्रतिशत जनसंख्या वास करती है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों यथा गैस, सोना, तांबे के विशाल भंडारों से युक्त है। किन्तु फिर भी यह क्षेत्र पाकिस्तान की मुख्यधारा से दूर अविकसित व आधारभूत सुविधाओं से वंचित है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय व प्रांतीय सरकारों की नीतियों ने इस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन तो भरपूर किया, किन्तु यहाँ के निवासियों को दमनपूर्वक इसके लाभों से दूर रखा। जिस कारण यहाँ के निवासी अपनी स्वायतत्ता के लिए अहिंसक एवं सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अपनी मागें मनवाने के लिए आंदोलनरत हैं। इस क्षेत्र में कई छोटे बड़े सशस्त्र विद्रोह होते रहे हैं।

इस तरह के विद्रोह पूर्व में हुए पूर्वी पाकिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य हुए भीषण नरसंहार और उसके फलस्वरूप बांग्लादेश के जन्म की याद दिलाता है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार इस विद्रोह की आवाज को दबाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है जोकि पाकिस्तान को एक अन्य विघटनकारी संघर्ष की ओर धकेल रहा है।

अफगानिस्तान :- अफगानिस्तान लंबे समय से बाहरी ताकतों के लिए एक रणनीतिक युद्ध क्षेत्र रहा है और ऐसा उसकी भू–आकृति के कारण है। जोकि उसे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया व दक्षिण एशिया के बीच एक रणनीतिक रूप से

महत्वपूर्ण राज्य का स्थान प्रदान करती है। साथ ही साथ विखंडित (Fragmented) और तरंगित (Polarised) स्वभाव के अफगान समाज के कारण जोकि विभिन्न नृजातीय समूह से बना है जोकि नेतृत्व के लिए आपस में ही संघर्षरत रहते है एवं बाहरी तत्वों से शक्ति प्राप्त करते है। यही कारण है कि पिछले 3 दशक से ज्यादा समय बीत जाने पर भी अफगानिस्तान में व्याप्त हालात आज वैश्विक चिंता का कारण बने हुए है।समय–समय पर यहाँ होने वाले तख्तापलट, सत्ता प्रमुख के किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित होकर कार्य करना, नियम–कानून व व्यवस्था निर्माण करना व दूसरे प्रमुख के आते ही सब बदल देना। इन सब प्रक्रियाओं ने एक राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया को न केवल बाधित किया बल्कि संघर्ष में बाहरी ताकतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का मौका भी दिया। लम्बे समय तक चले सत्ता संघर्ष, नागरिक संघर्ष व आतंक के विरुद्ध, संघर्ष ने अफगानिस्तान के लिए वर्तमान में हर क्षेत्र में चुनौती खड़ी कर दी है।यहाँ पर महिलाएँ आधुनिकता और परम्परा के बीच विवाद का विषय बन गयी हैं। तालिबान द्वारा इनसे वह आजादी छीन ली गई जो इन्हें 1960 व 70 के दशक में प्राप्त थी। इनको शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। 2001 के युद्ध के बाद कुछ उम्मीदें थीं किन्तु वह फलीभूत नहीं हुई। महिला केन्द्रित मुद्दों पर बमुश्किल चर्चा होती है, खासकर तालिबान शासन के दौरान पीड़ित महिलाओं पर।

आज वहाँ लोकतांत्रिक सरकार कार्य कर रही है फिर भी कुछ चुनौतियाँ चिंता का विषय हैं जो संघर्ष को विस्तारित कर सकती है।

- 11/9 व अमरीका का आतंकवाद के विरूद्ध युद्ध
- इस्लामिक राज्य की स्थापना

बांग्लादेश :- नौ महीने के खूनी युद्ध के बाद 1971 में बांग्लादेश की स्थापना एक स्वतंत्र देश के रूप में हुई। उस समय तक वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था जोकि पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हज़ारों जानें गई व लाखों लोगों ने भारत में शरण ली।

अपनी स्वतंत्रता के बाद भी बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य विद्रोह से जूझता रहा है। 1991 में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से आज तक बांग्लादेश के नागरिक विभिन्न समस्याओं व संघर्ष से जूझ रहे हैं।

बाग्लादेश में समय–समय पर सेना द्वारा तख्तापलट की कोशिश कहीं न कहीं इस बात का इशारा है कि सेना में सत्ता के प्रति आकर्षण हे महत्वाकांक्षी है। नवम्बर 1975, मार्च 1982, दिसम्बर 1990 तथा मई 1996 और 11 जनवरी 2007 में बांग्लादेश में सरकार का तख्तापलट करने की कोशिश की गई। शायद इसी कारण से बांग्लादेश में सेना को 'तीसरा बल' कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त देश के दोनों प्रमुख दलों की प्रमुखों के मध्य राजनीतिक दुराव जगजाहिर है जो कि समय–समय पर वहाँ सत्ता में आने पर एक–दूसरे की नीतियों को खत्म करने व बदलने के रूप में प्रदर्शित भी होता है।

राजनीतिक क्षेत्र में व्याप्त संघर्ष से इतर जो समस्या इन दिनों बांग्लादेश के साथ–साथ इस क्षेत्र की शांति व सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है या इससे बढ़कर आगे यह कहें की अपने विकराल रूप को पाने की ओर बढ़ रही है वह है बांग्लादेश में ISIS की उपस्थिति तथा देश में बढ़ता इस्लामी कट्टरपंथ।

देश में बढ़ती हुई कट्टरता भी महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर रही है और यह विडंबना का विषय है कि सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों की प्रधान महिलाएं ही हैं, किंतु पुरूष संरचनावादी समाज में यह स्वतंत्रता के साथ प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है।

देश में अल्पसंख्यकों व बहुसंख्यकों के बीच के विवाद की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएँ हैं। सुश्री तसलीमा नसरीन ने अपने उपन्यास ''लज्जा'' में इसका उल्लेख भी किया है।

हाल के वर्षों में बांग्लादेश में इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा देश के पंथनिरपेक्ष व वैचारिक खुलेपन के पक्षधर लेखकों, ब्लागर (Bloggers) एवं प्रकाशकों पर हमलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। जिससे इस देश में चरमपंथी संघर्ष की झलक मिलती है जोकि इस क्षेत्र व स्वंय बांग्लादेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसके अतिरिक्त जुलाई 2016 में ढाका में हुए आतंकी हमलों में ISIS की भूमिका भविष्य में अवांछित संघर्ष का संकेत है। समय रहते इस के लिए प्रभावी निवारक कदम नहीं उठाए गए तो इराक के मोसूल या बसरा में ISIS की कारगुजारी के गवाह रहे यह शहर बांग्लादेश में ढाका अथवा किसी अन्य शहर के रूप में ISIS के आतंकी कृत्यों के साक्षी बनेगें।

नेपाल :- दक्षिण एशियाई महाद्वीप के इस छोटे से भू–आबद्ध हिमालयी देश ने अपने शुरूआती पारंपरिक राजशाही शासन को खत्म कर अब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना लिया है किंतु नेपाल की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्याप्त अव्यवस्था

वर्तमान में वहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। देश में राजनीतिक अस्थिरता ने पूर्व की समस्याओं को तथा विकास की योजनाओं को अवरूद्ध कर दिया है।

संविधान निर्माण के दौरान राजनीतिक दलों का आपस में सामंजस्य न होना, बहुभाषाई नीति को परस्पर समानता न देना, आरक्षण में भेदभावपूर्ण प्रावधान ये सब ऐसे कारण है जो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था अपनाने वाले देश में भविष्य में किसी संघर्ष को जन्म दे सकता है। मधेसी विरोध व आंदोलन को हम इसका संकेत मान सकते हैं तो पूर्व में हुए माओवादी संघर्ष का इतिहास भी इस देश को भविष्य में किसी प्रकार के संघर्ष को रोकने की सीख दे सकता है।

श्रीलंका :- सन् 2009 में LTTE व सरकार के मध्य जारी छापामार हिंसक युद्ध की समाप्ति के साथ एक रक्तरंजित लम्बे नागरिक युद्ध का अंत हुआ जोकि एक नृजातीय तनाव (बौद्ध सिंहलीं व हिंदू तमिलों के मध्य) की उपज था। इस संघर्ष में लगभग 80,000 to 100,000 नागरिकों की मौत हुई व हज़ारों पलायन करने पर मज़बूर हुए।

किंतु वर्तमान में LTTE व सरकार के बीच हुए हिंसक युद्ध के पश्चात् इस क्रूरता से बचे लोगों के उचित पुर्नवास की समस्या है जो कि श्रीलंका के साथ–साथ भारत की भी चिंता है क्योंकि तमिलों की समस्या हमेशा से भारत की घरेलु राजनीति को प्रभावित करती है जिसका प्रभाव भारत–श्रीलंका के मध्य सम्बंधों पर भी पड़ता है। भारत श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर तमिलों के पुर्नवास में मदद कर रहा है।

चीन का अपनी 'String of Pearls' योजना के तहत श्रीलंका के विकास में भागीदार बनने की उत्सुकता, वर्तमान में इस क्षेत्र में एक प्रभावी रणनीतिक भूमिका के

तौर पर देखा जा सकता है जो कि इस क्षेत्र में शक्ति–संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जिसके फलस्परूप यह क्षेत्र अफगानिस्तान की भांति बाहरी शक्तियों के खेल का अखाड़ा बन सकता है।

मालद्वीव–1200द्वीपों की माला से बना मालदीव वर्तमान में दो बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है। प्रथम पर्यावरणी समस्याएं:– ग्लोबल वारमिंग के चलते समुद्र के बढ़ते स्तर ने इस देश के समक्ष अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी कर दी है। यह अपने–आप में एक तरह का संघर्ष है भले ही यह संघर्ष पर्यावरणीय स्तर पर है किन्तु इसके दुष्परिणाम की भयावहता एवं इसके प्रभाव की व्याप्कता से इंकार नहीं किया जा सकता। वस्तुतः इसी कारण से मालदीव की सरकार ने विश्व का ध्यान इस समस्या के प्रति आकर्षित करने तथा अपनी चिंता को प्रकट करने के लिए 17 अक्टूबर 2009 में पानी के अंदर कैबिनेट की बैठक की थी। वहीं दूसरी चुनौती के रूप में इस देश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता ने भी विश्व का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम तथा निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के बीच राजनीतिक दुराभाव व गतिरोध ने एक संकट का रूप ले लिया है जिसने देश की अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों को भी क्षति पहुँचाई है इसके अतिरिक्त मालदीव में चीन की बढ़ती दिलचस्पी व पर्दे के पीछे से हस्तक्षेप ने भारत के लिए भी सुरक्षा चिंता पैदा कर दी है।

भारत–दक्षिण एशिया के प्रमुख देश के रूप में भारत अपने क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों लिहाज से इस क्षेत्र के अन्य देशों से बड़ा है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 05
March 2018

1947 में अपनी आजादी व 1951 में गणतंत्र बनने के बाद से लेकर अब तक तीन–तीन युद्धों के पश्चात भी, दो निर्वाचित प्रधानमंत्रियों की नृशंसा हत्या के बावजूद लोकतंत्र अपनी अबाध गति से चल रहा है।

किंतु इस सफल लोकतांत्रिक यात्रा में कई ऐसे बिंदु हैं जो संघर्ष का कारण हैं अथवा भविष्य में किसी प्रकार के संघर्ष का कारण बन सकते है।

इनमें सबसे प्रमुख है कश्मीर की समस्या यह सर्वविदित है कि 1947 से लेकर आज 2018 तक कश्मीर की समस्या जस की तस है। कभी सक्रिय युद्ध द्वारा तो कभी अघोषित युद्ध या प्रायोजित आतंकवाद द्वारा इस क्षेत्र में अशांति व्याप्त करने की कोशिशें जारी रही हैं।

कश्मीर में आतंकवादी हमलों की कड़ी में सबसे ताजा हमला 'सुजवान मिलिट्री कैंप' जम्मू में 10 फरवरी 2018 का है। हमलों की फेहरिस्त लम्बी है और उससे भी लम्बी फेहरिस्त है इन हमलों में मारे गए निर्दोष लोगों की।

कश्मीर में अलगाववादी गुटों द्वारा पत्थरबाजी, बंद व हड़ताल का असर यहाँ आम जनजीवन पर साफ दिखाई देता है।

आतंकवाद एवं अलगाववाद के इस संघर्ष ने भारत विशेषकर जम्मू एवं कश्मीर राज्य को कड़ी चोट पहुँचाई है। विशेषकर राज्य में महिलाएं जो दोतरफा संघर्ष एवं अत्याचार का शिकार होती हैं।

वार्ताओं के द्वारा कश्मीर मसले के हर शांतिपूर्ण पहल पर आतंकी कृत्यों की चोट वार्ता की गति को बाधित कर देती है जिससे संघर्ष की स्थिति जस की तस

बनी हुई है उस पर सीमा पर दोनों सेनाओं के मध्य होने वाली गोलीबारी स्थानीय लोगों में भय का संचार करती है।

इसके साथ ही साथ उत्तर–पूर्व में स्थानीय व प्रवासियों के मध्य तनाव व देश के कुछ राज्यों के सीमित क्षेत्र में नक्सल आतंकवाद की समस्या चिंताजनक है।

इनके अतिरिक्त सांप्रदायिक सौहार्द का क्षरण करने वाली चंद घटनाएं, बढ़ती वैचारिक कट्टरता तथा अल्पसंख्यों पर हमले इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं जोकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष छवि वाले देश में अगर घटती हैं तो वह वास्तव में चिंताजनक है और कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि 'अनेकता में एकता' के सूत्रवाक्य को धारण करने वाले इस देश में यह सूत्र वास्तव में अपना अर्थ न खो दे।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ है सभी धर्मो एवं विचारों की आजादी है ऐसे में कुछ लोगों द्वारा किसी धर्म विशेष, खास विचारधारा को संस्कृति के नाम पर आगे बढ़ाकर एक धर्म एक राष्ट्र का निर्माण करने की अवधारणा इस देश में संघर्ष का बीज बोकर इसे खण्डित कर सकते हैं।

वैचारिक आजादी, सम्प्रदायिक सौहार्द, अल्पसंख्यक हित, धर्मनिरपेक्षता यह सब कुछ ऐसे विषय हैं जो कि संवेदनशील हैं तथा पूर्व में छोटे बड़े टकराव का कारण बने हैं। इन मूल्यों का क्षरण किसी भी बड़े संघर्ष का सूत्रपात कर सकते हैं जो कि भारत की लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर कर इसके स्वरूप को हानि पहुँचा सकते हैं।

दक्षिण एशिया में व्याप्त संघर्ष के पीछे कारण–

दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में हमें जो आज संघर्ष दिखाई देता है उसकी दो मुख्य वजहें हम पाते हैं– (i) औपनिवेशिक विरासत एवं (ii) आज़ादी के पश्चात् राष्ट्र निर्माण/राज्य निर्माण की अशांत प्रक्रिया।

औपनिवेशिक विरासत के अंतर्गत हम तीन कारणों को रेखांकित कर सकते हैं (i) असंगत राज्य शासन व्यवस्था (ii) सीमाओं का अस्पष्ट व आधा–अधूरा सीमांकन (iii) नृजातीय विविधता, धार्मिक अल्पसंख्यकों व सामाजिक समूहों की प्रस्थित (Status) की अनदेखी।

दक्षिण एशिया के घरेलू संघर्ष की जड़े इसके क्षेत्रों में राज्य निर्माण की अशांत व उग्र प्रक्रिया में भी निहित है। अनियोजित सामाजिक समीकरण एवं राजनीतिक पदसोपान ने इस नृजातीय व वर्गीय संघर्ष को और तेज धार प्रदान की है। पहचान व राज्य के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण में खुद की पहचान बनाने की चाहत ने इस क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य संघर्ष के बीज बो दिए हैं। एक अनिश्चित पहचान के बीज पाकिस्तान के निर्माण में जोर–शोर से पंजाबियों की भागीदारी एवं उन्हें सिंधि, बलूची और पठानों के ऊपर प्रधानता देना, श्रीलंका में 1959 के भाषायी कानून द्वारा सिंहली, बौद्धों द्वारा तमिल एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्गों की संवेदनाओं को दरकिनार कर देना ही इन देशों में गंभीर आंतरिक संघर्ष की वजह बना।

भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आजादी के 70 वर्षों बाद भी सामाजिक रूप से पिछड़े व अशक्त वर्गों का विकास एक चुनौती के रूप में विद्यमान हैं। विकास की तेज प्रक्रिया में नजरअंदाज व असमानता के शिकार इन वर्गों ने राजनीतिक नेतृत्व पर विभिन्न तरह से दबाव डाला है। विकास के लाभों एवं संसाधनों के असमान

वितरण ने संकलन (Acquisition) एवं अभिलाषा (Aspiration) वर्ग के बीच दरार को बढ़ाया है जोकि संघर्ष का एक कारक है।

पिछले 10 सालों से नेपाल में माओवादी संघर्ष (1996 से 2006) उपेक्षित जनजातीय व स्थानीय समूहों द्वारा चलाया जा रहा था जो अब 'नए नेपाल' में अपने लिए समान व सम्मानित स्थान (Status) की मांग कर रहे हैं।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त दक्षिण एशिया क्षेत्र के अप्राकृतिक व खुले सीमा क्षेत्रों के कारण अतीत की नृजातीय व साझी संस्कृति किसी भी क्षेत्र में होने वाले संघर्ष को आसानी से अपने निकटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करती है अथवा उसका विस्तार कर देती है।

दक्षिण एशिया में संघर्ष के क्या निहितार्थ होंगें–

- सांस्कृतिक मेल–मिलाप किसी भी संस्कृति को सांस्कृतिक रूप से संवर्धित (Enrichment) करते हैं जिसमें एक अन्य संस्कृति के मूल्यों को अपना लेती है किंतु जब इन्हीं में खासकर धर्म के ईर्द–गिर्द संघर्ष की स्थिति जन्म लेती है तो वह कट्टरवाद को बढ़ावा देती है जो रूढ़िवाद को प्रसारित करता है और एक कट्टर सोच को पोषित करता है जो कि समाज में विभाजन को जन्म देता है।

- अधिकांशतः मामलों में रूढ़िवाद सोच महिलाओं को अहितकारी स्थिति में पहुँचा देती है जहाँ पुरूषों द्वारा उनकर अपनी श्रेष्ठता को जबरन थोप दिया जाता है। इस प्रकार महिला स्वतः ही पुरूष का दायित्व बन जाती है और उस पर आश्रित हो जाती है।

- महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी, बलात्कार, अप्रवासन व पुनर्वास, युद्ध और संघर्ष से उजड़े क्षेत्र की सामान्य लक्षण हैं यह क्षेत्र में जनसांख्यिकीय अस्थिरता एवं क्षेत्रीय अशांति को उत्पन्न करता है।

- किसी क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति व परिस्थिति उसके (क्षेत्र के) विदेशी सम्बन्धों पर भी असर डालती है उदाहरण के लिए– म्यामांर के रखाइन प्रान्त के रोहिंग्या पर अत्याचार। इन अत्याचारों के तहत रोहिंग्या को वहाँ से बलपूर्वक भगाया गया एवं पड़ोसी देशों में (बांग्लादेश और भारत) में शरण लेने पर मजबूर किया। बांग्लादेश ने तत्काल ही इस समस्या पर अपनी चिन्ताओं को व्यक्त किया तथा म्यामार को संघर्ष को रोकने की सलाह दी।

- आर्थिक क्रिया कलाप यथा उत्पादन व आपूर्ति पर भी संघर्ष का असर पड़ता है। जिसके कारण जरूरत की चीजों की किल्लत स्थिति को एक और संघर्ष में बदल देती है, जो कि परिस्थिति को बद से बदतर बना देता है।

- अशांत व संघर्षरत क्षेत्र की सरकारें अपने अधिकांश संसाधन रक्षा व शांति स्थापना के लिए प्रयुक्त करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक विकास के क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली धनराशि या तो कम कर दी जाती है अन्यथा फिर खत्म कर दी जाती है।

- संघर्ष एवं अशांत क्षेत्र अमूमन आतंकी तत्वों का जन्मस्थान व पनाहगाह बन जाते हैं और ऐसे तत्व केवल उस क्षेत्र के लिए ही नहीं अपितु पूरी मानवता के लिए खतरा (भय) का कारण बना जाते हैं।

- अधिकांश अशांत व संघर्षरत क्षेत्र अपने यहाँ राजनीतिक अस्थिरता व प्रशासनिक अक्षमता/कुप्रशासन को जन्म देते हैं, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसके उदाहरण हैं।

निष्कर्ष –

दक्षिण एशिया के समस्त देश पूर्व में एक–दूसरे से जुड़े रहे हैं। इन देशों का एक साझा इतिहास व एक साझी संस्कृति रही है जो कि इस क्षेत्र की हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के इतिहास में दृष्टिगत होती है।

किन्तु समय के साथ इन देशों के मध्य अविश्वास की भावना ने जन्म लिया। देशों के भीतर ऐसे कारक रहे जिन्होंने संघर्ष को जन्म दिया। संघर्षों के प्रकार, उसके लिए उत्तरदायी कारको तथा उसके होने वाले परिणामों की चर्चा अध्याय में हो चुकी है। यह तो स्पष्ट है कि दक्षिण एशियाई देशों की अलग–अलग अपनी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का अपना अलग स्परूप है किंतु यह क्षेत्र दो और चिंताजनक स्थिति को वृहद तौर पर साझा करता है प्रथम आतंकवाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान आतंकवाद से पीड़ित हैं। आतंकवाद इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और दूसरी समस्या जो विडंबना का विषय है वह यह कि दक्षिण एशिया में व्याप्त संघर्षों में तो महिलाएं पुरूषों के समान तो कहीं–कहीं उनसे ज्यादा संख्या में पीड़ित हैं किन्तु बात जब समाधान की होती है तब महिलाओं की संख्या बराबर तो दूर संतोषजनक संख्या में भी नहीं होती। फिर बात चाहे नेपाल में लोकतंत्र स्थापना की प्रक्रिया की हो जहाँ माओवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका नजर आती है किंतु जब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इन महिलाओं की उपस्थिति लगभग नगण्य व अप्रभावी थी। इसी प्रकार कश्मीर समस्या को हमेशा पुरूषवादी चर्चा के संदर्भ में देखा गया जबकि कटु सत्य यह है कि कश्मीर समस्या में वहाँ की महिलाएं भी पीड़ित हैं किन्तु इस

समस्या पर होने वाली किसी भी वार्ता में हमें महिलाएं अनुपस्थित नजर आती हैं।

लैंगिक असमानता दक्षिण एशियाई देशों में व्याप्त अपने–आप में अलग समस्या और एक अन्य स्तर पर खुद में संघर्ष का विषय है किंतु कहीं–न–कहीं यह विषय सशस्त्र संघर्षों व अन्य धार्मिक–वैचारिक संघर्षों से प्रभावित होता है। अतः ऐसे में यह जरूरी है कि समस्या के समाधान में सबकी बराबर की भूमिका हो तभी इस क्षेत्र में विकास द्वारा संपन्नता एवं शांति की स्थापना संभव होगी।

Bibliography

Adhikari Shekhar, (2014) South Asia: Traditional and Non-Traditional Security Threats, Pentagon Press.

Adhikari Shekhar, (2015) India's Security Interest in Her Neighborhood, Pentagon Press.

Adhikari Shekhar, Bhadauria Sanjeev, (2014) India's "national security in the 21st century", Pentagon Press.

Allen Douglas, (1992) Religion and Political Conflict in South Asia: India, Pakistan, and Sri Lanka, Greenwood Press.

Bhasin Avtar Singh, (2008) India In Sri Lanka Between Lion And The Tigers, Manas Publications.

Bandarage Asoka, (2009) The Separatist Conflict in Sri Lanka: Terrorism, Ethnicity, Political Economy, Iuniverse Star.

Chandran D. Suba, Chari P.R, (2013) Armed Conflicts in South Asia, Routledge publications New Delhi .

Chatterji Manas, Singh Savita, (2011) Governance, Development and Conflict, Emerald Group Publishing.

Chester Lucy P, (2013) Borders and Conflict in South Asia: The Radcliffe Boundary, Manchester University Press.

Dixit J.N, (1998) Assignment Colombo, Konark Publishers Pvt Ltd.

Dutt, V.P (1998) "India foreign policy in a changing world" Vikas publishing house Pvt.Ltd.

Ghosh Partha Sarathy, (1989) Cooperation and Conflict in South Asia, Technical publications.

Gupta C Das, (2002) War and Diplomacy in Kashmir, 1947-48, SAGE publications.

Jonathan Spencer (E.d.) (1990) Sri Lanka HISTORY AND THE ROOTS OF CONFLICT, Routledge Publication.

MEHTA J.N, (2015) China and South Asia Strategy In 21st century Neha publishers.

Shahi & singh, (2016) Perspectives on India's National Security Challenges: External and Internal Dimensions, Pentagon Press.